

अनुदान संख्या 44 – भारी उद्योग विभाग
GRANT No. 44 - DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	930,35,00		
		972,81,00	584,98,68	-387,82,32
पूरक	Supplementary	42,46,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			387,65,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	559,63,00		
		559,64,00	311,56,00	-248,08,00
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			248,07,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹38782.32 लाख) सितंबर, 2020 तथा फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹4246.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹38782.32 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹4246.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and constituted 40 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”			
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	4109.00		
			3254.84	3238.60
पु.	R.	-854.16		-16.24
मुख्य शीर्ष “2852”	Major Head “2852”			
उद्योग	Industries			
मू.	O.	88926.00		
पू.	S.	4246.00	55261.16	55260.08
पु.	R.	-37910.84		-1.08

(I) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – भारी उद्योग विभाग” के अंतर्गत ₹870.40 लाख की बचत (₹4109.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने तथा कोविड-19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष “2852” – “सामान्य – अन्य व्यय” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “ऑटो मोबाइल उद्योग का विकास” – ₹37607.49 लाख की बचत (₹70794.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का विकास” – ₹10704.43 लाख की बचत (₹17931.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड-19 महामारी के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(I) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Department of Heavy Industry” - saving of ₹870.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4109.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(II) Under Major Head “2852” - “General - Other Expenditure” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Development of Automobile Industry” - saving of ₹37607.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70794.00 lakhs); and

(B) “Development of Capital Goods Sector” - saving of ₹10704.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17931.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from implementing agencies owing to COVID -19 pandemic.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹10401.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष “2852” – “सामान्य” – अन्य व्यय – केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹10400.00 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः-

2. The above savings were partly (₹10401.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head “2852” - “General - Other Expenditure - Support to Central Public Sector Enterprises”. Actual excess, however, was ₹10400.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष “4860” उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4860” Capital Outlay on Consumer Industries			
मू.	O.	14224.00		
पु.	R.	-4929.00	9295.00	9295.00
मुख्य शीर्ष “6858” इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head “6858” Loans for Engineering Industries			
मू.	O.	35399.00		
पू.	S.	1.00	15531.00	15530.00
पु.	R.	-19869.00		-1.00

(I) ₹5907.00 लाख का प्रावधान सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹5392.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष “6858” – “अन्य इंजीनियरी उद्योग – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज – स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा पृथकीकरण स्कीम (वीआरएस/वीएसएस) का कार्यान्वयन तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान” – कोविड-19 महामारी

(I) Provision of ₹5907.00 lakhs remained wholly unutilized under seventeen heads; of these ₹5392.00 lakhs alone accounted for under Major Head “6858” - “Other Engineering Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Implementation of Voluntary Retirement and

के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष “4860” – “पेपर और न्यूजप्रिंट – सावर्जनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – नेपा मिल्स लि. में निवेश” के अंतर्गत – ₹4429.00 लाख की बचत (₹13724.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष “6858” – “अन्य इंजीनियरी उद्योग – अन्य ऋण – नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग तथा आरएंडडी अवसंरचना परियोजनाओं को कर्ज” के अंतर्गत ₹18570.00 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड-19 महामारी के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4099.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष “6858” – “परिवहन उपकरण उद्योग – सावर्जनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज – स्कूटर इंडिया लिमिटेड को कर्ज” के अंतर्गत फरवरी, 2021 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹4098.00 लाख था।

Separation Scheme (VRS/VSS) and Payment of Statutory Dues” - due to non-receipt of proposals from implementing agencies owing to COVID-19 pandemic.

(II) Under Major Head “4860” - “Paper and Newsprint - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Investment in Nepa Mills Ltd.” - saving of ₹4429.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13724.00 lakhs); and

(III) Under Major Head “6858” - “Other Engineering Industries - Other Loans - Loans to National Automotive Testing and R&D Infrastructure Projects” - saving of ₹18570.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from implementing agencies owing to COVID-19 pandemic.

4. The above savings were partly (₹4099.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2021 under Major Head “6858” - “Transport Equipment Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Scooter India Limited”. Actual excess, however, was ₹4098.00 lakhs.